

विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। -अज्ञात

आग चाहिए, जोखिम नहीं प्रमथ्यु की प्रतीक्षा में बैठा समाज

हम कुछ मित्र हर शाम एक पार्क में मिलते हैं। अपने सुख दुख की बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, दुनिया जहान की बातें करते हैं। बातचीत में समकालीन प्रसंग भी आ ही जाते हैं। देश और दुनिया में इतना कुछ घटित होता रहता है, उससे अछूता और अप्रभावित रहना लगभग नामुमकिन होता है। कभी प्रश्नाचार की तो कभी बेरोजगारी की, कभी पेपर लीक की तो कभी मंदिर के तथाकथित आर्थिक चोटाले की, कभी सांप्रदायिकता की तो कभी स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार की, कभी अताकिंक गोपनीयता की तो कभी उजागर हुए घपलों की या ऐसे ही किसी मुद्दे की चर्चा होने लगती है। हर चर्चा में बहस होती है, उत्तेजन होती है, स्पष्ट रूप से पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन मैंने यह बात नोट की है कि अगर मुझ सरकार से जुड़ा हो तो हर बार कोई न कोई मित्र एक सवाल जरूर उठाता है: "विपक्ष क्या कर रहा है? और अगर कभी चर्चा सरकार से इतर किसी मुद्दे की चले तो एक अन्य वाक्य सुनने को मिल जाता है: "किसी को तो आगे आना चाहिए!"

जब भी ऐसा होता है, अनायास मुझे यूनानी मिथकीय चरित्र प्रमथ्यु याद आ जाता है। बहुत संक्षेप में बताऊं तो यह कि प्रमथ्यु देवताओं से अनिन चुराकर मनुष्यों को देता है। यहां अग्नि केवल आग नहीं है, वह ज्ञान, तकनीक, विवेक, सभ्यता और स्वतंत्रता की प्रतीक है। प्रमथ्यु की इस 'चोरी' के लिए देवताओं के राजा ज्यूस उसे बहुत कठोर दण्ड देते हैं। दण्ड यह है कि उसे एक चट्टान से बांध दिया जाता है और प्रतिदिन एक गिद्ध उसका कलेजा चोचता है। यह कथा हमें बताती है कि प्रमथ्यु द्वारा चुरा कर लाई हुई आग का लाभ तो पूरी मानवता ने उठाया है लेकिन दंड अकेले प्रमथ्यु ने भुगता। इस कथा को हिंदी कवि धर्मवीर भारती ने अपनी लम्बी कविता 'प्रमथ्यु गाथा' में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। उसे तलाश करके जरूर पढ़ें।

प्रमथ्यु की यह कथा मैंने इसलिए याद की कि 'लाभ तो हम सब उठाएँ लेकिन उसका मोल कोई एक ही चुकाए' की यह मानसिकता आज की नहीं है। अगर अपने समाज को थोड़ी बारीक नज़र से देखें तो कोई भगत सिंह हो, कोई महात्मा गांधी हो, कोई जयप्रकाश नारायण हो, कोई अरुणाराय हो, कोई भी विह्वलब्लोअर हो - दूसरा ही हो। हम तो बस सवाल उठाते रहें कि अमुक क्या कर रहा है! सडक पर कचरा पड़ा हो, जो हमने ही बिखेरा है, तब भी हम सरकार को कोसने से बाज नहीं आते हैं। सडक पर अतिक्रमण होते देखते हैं, देखते क्या मौका लगते ही खुद भी कर लेते हैं, लेकिन पूछते हैं कि सरकार अतिक्रमण क्यों नहीं हटाती है। हम जात-पात, सांप्रदायिकता, धर्मांधता, बेहदगी, बदतमीजी, बेईमानी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी सब में लिप्त रहते हैं लेकिन यह सवाल पूछने से खुद को कभी नहीं रोकते कि इस मामले में अमुक क्या कर रहा है?

कभी सोच कर देखें, सरकार क्या है, विपक्ष क्या है? क्या ये हमसे अलग हैं? भारत जैसे प्रजातंत्र में क्या हम ही सरकार नहीं हैं? क्या हम ही विपक्ष नहीं हैं? कभी हमने यह भी सोचने का कष्ट किया है कि हम क्या कर सकते थे, और हमने क्या नहीं किया! एक नागरिक के रूप में हम भी तो सूचना के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, हम भी तो जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, हम भी तो प्रश्नाचार के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, हम भी तो मुनाफाखोरी के विरुद्ध बोल या लिख सकते हैं, हम भी तो पर्यावरण को बचाने में अपना योग दे सकते हैं। हम अपनी मायद भासा राजस्थान की मान्यता के लिए सरकार को गरियाते रहते हैं, लेकिन हम खुद उसे बरतने में कृपणता दिखाते हैं। हम यह कहते नहीं थकते कि आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं, हम कभी यह सवाल नहीं करते कि हम खुद कितना पढ़ते हैं! हमारी सारी शिकायतें और सारी अपेक्षाएं दूसरों से होती हैं। दूसरों से अर्थात् सरकार से, विपक्ष से, मीडिया से, स्वयंसेवी संगठनों से, पड़ोसियों से - और भी न जाने किन-किन से। बस, अपने गिरेबां में झाँककर देखने से हम चूक जाते हैं।

असल में बात यह है कि दोष केवल सरकार का या विपक्ष का या मीडिया का या धर्म का या सामाजिक संगठनों का नहीं है। मैं इन सबको थोक में क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आपको यह सोचने के लिए कह रहा हूँ कि क्या हमारी अपनी मानसिकता यह नहीं है कि जो करना है वह कोई और करे। मेहनत कोई और कर, जोखिम कोई और उठाए, कीमत कोई और चुकाए, बदनामी कोई और सहे, पप्पू कोई और कहलाए, टॉटी चोर किसी और को कहा जाए, उपहास का पात्र कोई और बने, जेल कोई और जाए, गोली कोई और खाए। लेकिन अगर स्थितियाँ बदलकर बेहतर हो जाएँ तो उसका लाभ हम लें। तब एक पल को ही यह न सोचें, कि इस बदलाव के लिए हमने क्या किया था!

भारत एक प्रजातंत्र है। अगर हम अतीत में न भी जाएँ तो लगभग साठे सात दशक से तो प्रजातंत्र ही हो। क्या हमने कभी यह सोचा है कि केवल हर पाँचवें साल जाकर मतदान कर आना प्रजातंत्र नहीं होता है। अपने प्रजातंत्र को जिंदा और सक्रिय रखने के लिए हमें और भी काफी कुछ करना होता है। हमें सवाल पूछने होते हैं, हमें स्थानीय समस्याओं पर आवाज़ उठानी होती है, हमें अपने जन प्रतिनिधियों से संवाद करना और उन्हें अपनी अपेक्षाओं से अवगत कराना होता है, उन्हें टोकना होता है, हमें जनहित के मुद्दों पर बातचरण बना होता है, हमें सही काम करने वालों को संबल प्रदान करना होता है। यह सही है कि आज जन प्रतिनिधियों तक पहुँच पाना आसान नहीं है। लेकिन जन प्रतिनिधियों की हमसे यह पूरी अचानक पैदा नहीं हुई है। इसमें हमारी निष्क्रियता का भी योगदान कम नहीं है। डॉ बशीर बद्र साहब का एक खूबसूरत शेर है: - 'सर झुकाओगे तो पत्थर देता हो जाएगा। इतना मन चाहो उसे को बेवफा हो जाएगा। अगर हमारे जन प्रतिनिधि हमारी पहुँच से बाहर हो गए हैं तो इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। हमने उन्हें ऐसा हो जाने दिया है।

हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर हममें से हरेक ही किसी और प्रमथ्यु की प्रतीक्षा करता रहेगा तो आग लाएगा कौन? यह सच है कि हर समाज को प्रमथ्यु की जरूरत होती है, और यह भी सच है कि हममें से हरेक प्रमथ्यु नहीं हो सकता। लेकिन क्या हम प्रमथ्यु का साथ देने वाले, उसे अपना सम्पन्न देने वाले, उसका उत्साह बढ़ाने वाले भी नहीं बन सकते? क्या हम प्रमथ्यु को दंडित करने वाले अत्याचारी अपने समाज में हम देखते हैं कि जो प्रमाणिक रूप से प्रष्ट हैं उनके प्रति भी हम अपनी स्पष्ट नापसंदगी व्यक्त नहीं करते हैं। आज तो हालत यह है कि हमें आग तो चाहिए, लेकिन आग लाने वाले के घावों की हम परवाह नहीं करते।

सवाल उठाना जरूरी है कि सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, न्यायपालिका, मीडिया और सामाजिक संगठन क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक प्रश्न और जुड़ना चाहिए- हम क्या कर रहे हैं? क्या हम स्वयं सवाल पूछ रहे हैं? क्या हम सही बात कहने वालों के साथ खड़े हैं? क्या हम उन लोगों का समर्थन करते हैं जो सार्वजनिक हित में जोखिम उठाते हैं? या हम केवल दर्शक बने रहना चाहते हैं?

कोई भी समाज इसलिए कमजोर नहीं होता कि उसके पास प्रमथ्यु कम है। वह तब कमजोर होता है जब वह अपने हर प्रमथ्यु को अकेला छोड़ देता है। इतिहास को आगे बढ़ाने वाले लोग हमेशा अल्पसंख्यक रहे हैं, लेकिन इतिहास की गति को रोकने वाली चीज बहुसंख्यक की उदासीनता रही है। यह उदासीनता टूटे और हममें से हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करे-शायद यही हमारे समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

-अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

एआई, रोजगार और बाज़ार: क्या दुनिया धीरे-धीरे एक साइलेंट मंटी की तरफ बढ़ रही है?



सुनील दत्त गोयल

आज दुनिया सिर्फ तकनीक के बदलने का दौर नहीं देख रही, बल्कि पूरी आर्थिक व्यवस्था बदलने के दौर से गुजर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन अब केवल आर्टिड कंपनियों तक सीमित चीज़ें नहीं रह गई हैं। बैंकिंग, मीडिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, ग्राहक सेवा, फैक्ट्री, लॉजिस्टिक्स और यहां तक कि क्रिएटिव फ़िल्ड में भी एआई तेजी से अपनी जगह बना रहा है।

कंपनियाँ इसे खर्च कम करने, तेज़ फैसले लेने और कम कर्मचारियों में ज्यादा काम करने के साधन के रूप में देख रही हैं। निवेशकों को भी इसमें भविष्य की अर्थव्यवस्था दिखाई दे रही है। लेकिन इसी उसाह के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है- क्या हम अनजाने में उस आर्थिक व्यवस्था को ही कमजोर कर रहे हैं, जिस पर पूरा बाज़ार टिका हुआ है?

असल में दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ मशीनों से नहीं चलती। उसका असली आधार आम आदमी की कमाई और उसका खर्च होता है। अगर तकनीकी तेजी से इंसानी नौकरियों की जगह लेने लगे और पैसा कुछ सीमित लोगों तक सिमटने लगे, तो आने वाले समय में दुनिया एक ऐसी साइलेंट रिसेशन यानी धीमी और अंदर ही अंदर बढ़ते वाली मंटी की तरफ जा सकती है, जिसका असर बहुत गहरा हो सकता है।

अर्थव्यवस्था का असली आधार: आम आदमी का खर्च अर्थशास्त्र का एक बहुत सीधा सिद्धांत है- जो व्यक्ति कमाता है, वही खर्च करता है और वही बाजार को चलाता है। इसे संकुचित फ्लो ऑफ़ इनकम कहा जाता है।

किसी कर्मचारी की सैलरी सिर्फ उसकी व्यक्तिगत कमाई नहीं होती। वही पैसा कितने की दुकान तक जाता है, मकान किराया बनता है, बच्चों की फीस बनता है, गाड़ी खरीदने में लगता है, अस्पताल, मोबाइल रिचार्ज, कपड़े और मनोरंजन तक पहुँचता है। यही पैसा आगे दूसरे लोगों की आय बन जाता है।

वर्ल्ड बैंक और आई एम एफ के अनुसार भारत की जीडीपी का लगभग 57 से 60 प्रतिशत अमेरिका के निजी खर्च से आता है। इसका जैसे

देशों में यह आँकड़ा लगभग 68 प्रतिशत तक है। इसका मतलब साफ है- अगर आम आदमी की कमाई कमजोर होती है, तो बाजार की मांग भी कमजोर होने लगती है।

यानी अर्थव्यवस्था केवल फैक्ट्री और उत्पादन से नहीं चलती, बल्कि लोगों की खरीदने की क्षमता से चलती है। और यह क्षमता सीधे रोजगार से जुड़ी होती है।

एआई से काम बढ़ रहा है, लेकिन नौकरियाँ घटने का डर भी बढ़ रहा है। एआई के समर्थक अक्सर कहते हैं कि हर नई तकनीक नई नौकरियाँ पैदा करती है। यह बात कुछ हद तक सही भी है। औद्योगिक क्रांति, कंप्यूटर और इंटरनेट ने भी नई संभावनाएँ पैदा की थीं। लेकिन एआई की गति और उसका दायरा पहले की तकनीकों से कहीं ज्यादा बड़ा है।

McKinsey Global Institute की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दुनिया में 40 से 80 करोड़ नौकरियाँ ऑटोमेशन से प्रभावित हो सकती हैं। वहीं का अनुमान है कि जनरेटिव एआई लगभग 30 करोड़ फुल-टाइम नौकरियों के बराबर काम को प्रभावित कर सकता है।

World Economic Forum का 'Future of Jobs Report 2023' 2023 कहती है कि अगले पाँच सालों में लगभग 23 प्रतिशत नौकरियाँ बदल जाएँगीं। करीब 619 करोड़ नई नौकरियाँ बनेंगीं, लेकिन 813 करोड़ नौकरियाँ खत्म भी हो सकती हैं।

सबसे बड़ा असर अब व्हाइट कॉलर जॉब्स पर दिखाई देने लगा है। पिछले दो सालों में हजारों कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है। कई कंपनियाँ खुलकर कह रही हैं कि वे कम कर्मचारियों और ज्यादा एआई वाले मॉडल पर जा रही हैं।

भारत के लिए यह खतरा ज्यादा बढ़ा क्यों है? भारत की स्थिति विकसित देशों से अलग है। यहाँ हर साल लाखों युवा नौकीरी की तलाश में बाजार में आते हैं। CMIE के अनुसार भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी कई बार 15 से 20 प्रतिशत तक दर्ज की गई है।

भारत में एक नौकीरी केवल एक व्यक्ति को कमाई नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार का सहारा होती है। ऐसे में अगर एआई शुरुआती स्तर की नौकरियों को तेजी से खत्म करने लगे, तो इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी होगा।

विशेष चिंता की बात यह है कि एआई सबसे पहले उन्हीं नौकरियों को प्रभावित कर रहा है, जो दोहराव वाले काम हैं। और भारत का सर्विस सेक्टर काफी हद तक इसी मॉडल पर आधारित है। BPO, बैंक ऑफिस, बेसिक कोडिंग, डेटा एंट्री और ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में करोड़ों युवा काम करते हैं। अगर कोई कंपनी पहले 100 कर्मचारियों से काम कर रही थी और अब 25-30 कर्मचारियों और एआई टूल्स से वही काम करने लगे, तो कंपनी का खर्च जरूर कम होगा। लेकिन बाकी लोगों की कमाई भी खत्म हो जाएगी। यहाँ से समस्या केवल रोजगार की नहीं रहती, बल्कि बाजार की मांग की बन जाती है।

2008 की मंटी ने दुनिया को क्या सिखाया था? 2008 की वैश्विक आर्थिक मंटी आज भी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक मानी जाती है। अमेरिका को सब-प्राइम लोन संकट और Lehman Brothers जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाओं के गिरने से पूरी दुनिया हिल गई थी।

लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब लोगों की नौकरियाँ गईं और खर्च कम होने लगा। लोगों ने घर खरीदना बंद किया, कार खरीदना बंद किया और खर्च सीमित कर दिया। बाजार में मांग घटी, तो उत्पादन भी घट गया और कंपनियों संकट में आ गईं। यानी अर्थव्यवस्था का असली इंजन आम आदमी का खर्च है। अगर लोगों की जेब कमजोर होती है, तो बड़े-बड़े उद्योग भी लंबे समय तक नहीं टिक सकते। आज का खतरा थोड़ा अलग है। यह अचानक आने वाला संकट नहीं है। यह धीरे-धीरे बढ़ने वाला देवाव है। इसलिए इसे साइलेंट रिसेशन कहा जा सकता है।

साइलेंट रिसेशन आखिर है क्या? साइलेंट रिसेशन ऐसी स्थिति होती है जहाँ ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। शेयर बाजार बढ़ रहा होता है, कंपनियों का मुनाफा भी अच्छा दिखता है, लेकिन जमीन पर लोगों की वास्तविक कमाई और नौकीरी की स्थिति धीरे-धीरे कमजोर होती जाती है। मान लीजिए कोई कंपनी एआई की मदद से अपने 70 प्रतिशत कर्मचारियों को हटाकर भी काम चलाने लगे। शुरुआती समय में कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है। निवेशक खुश होंगे। शेयर की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

लेकिन वे 70 प्रतिशत लोग जो पहले वेतन पा रहे थे, अब बाजार में पहले जैसे ग्राहक नहीं रहेंगे। वे नया घर खरीदने से बचेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बच्चों की महंगी पढ़ाई कम करेंगे और खर्च घटा देंगे।

धीरे-धीरे इसका असर हर क्षेत्र में फैलने लगेगा।

सामाजिक भी होगा।

विशेष चिंता की बात यह है कि एआई सबसे पहले उन्हीं नौकरियों को प्रभावित कर रहा है, जो दोहराव वाले काम हैं। और भारत का सर्विस सेक्टर काफी हद तक इसी मॉडल पर आधारित है। BPO, बैंक ऑफिस, बेसिक कोडिंग, डेटा एंट्री और ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में करोड़ों युवा काम करते हैं। अगर कोई कंपनी पहले 100 कर्मचारियों से काम कर रही थी और अब 25-30 कर्मचारियों और एआई टूल्स से वही काम करने लगे, तो कंपनी का खर्च जरूर कम होगा। लेकिन बाकी लोगों की कमाई भी खत्म हो जाएगी। यहाँ से समस्या केवल रोजगार की नहीं रहती, बल्कि बाजार की मांग की बन जाती है।

2008 की मंटी ने दुनिया को क्या सिखाया था?

2008 की वैश्विक आर्थिक मंटी आज भी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक मानी जाती है। अमेरिका को सब-प्राइम लोन संकट और Lehman Brothers जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाओं के गिरने से पूरी दुनिया हिल गई थी।

लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब लोगों की नौकरियाँ गईं और खर्च कम होने लगा। लोगों ने घर खरीदना बंद किया, कार खरीदना बंद किया और खर्च सीमित कर दिया। बाजार में मांग घटी, तो उत्पादन भी घट गया और कंपनियों संकट में आ गईं। यानी अर्थव्यवस्था का असली इंजन आम आदमी का खर्च है। अगर लोगों की जेब कमजोर होती है, तो बड़े-बड़े उद्योग भी लंबे समय तक नहीं टिक सकते। आज का खतरा थोड़ा अलग है। यह अचानक आने वाला संकट नहीं है। यह धीरे-धीरे बढ़ने वाला देवाव है। इसलिए इसे साइलेंट रिसेशन कहा जा सकता है।

साइलेंट रिसेशन आखिर है क्या? साइलेंट रिसेशन ऐसी स्थिति होती है जहाँ ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। शेयर बाजार बढ़ रहा होता है, कंपनियों का मुनाफा भी अच्छा दिखता है, लेकिन जमीन पर लोगों की वास्तविक कमाई और नौकीरी की स्थिति धीरे-धीरे कमजोर होती जाती है। मान लीजिए कोई कंपनी एआई की मदद से अपने 70 प्रतिशत कर्मचारियों को हटाकर भी काम चलाने लगे। शुरुआती समय में कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है। निवेशक खुश होंगे। शेयर की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

लेकिन वे 70 प्रतिशत लोग जो पहले वेतन पा रहे थे, अब बाजार में पहले जैसे ग्राहक नहीं रहेंगे। वे नया घर खरीदने से बचेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बच्चों की महंगी पढ़ाई कम करेंगे और खर्च घटा देंगे।

धीरे-धीरे इसका असर हर क्षेत्र में फैलने लगेगा।

विशेष चिंता की बात यह है कि एआई सबसे पहले उन्हीं नौकरियों को प्रभावित कर रहा है, जो दोहराव वाले काम हैं। और भारत का सर्विस सेक्टर काफी हद तक इसी मॉडल पर आधारित है। BPO, बैंक ऑफिस, बेसिक कोडिंग, डेटा एंट्री और ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में करोड़ों युवा काम करते हैं। अगर कोई कंपनी पहले 100 कर्मचारियों से काम कर रही थी और अब 25-30 कर्मचारियों और एआई टूल्स से वही काम करने लगे, तो कंपनी का खर्च जरूर कम होगा। लेकिन बाकी लोगों की कमाई भी खत्म हो जाएगी। यहाँ से समस्या केवल रोजगार की नहीं रहती, बल्कि बाजार की मांग की बन जाती है।

2008 की मंटी ने दुनिया को क्या सिखाया था?

2008 की वैश्विक आर्थिक मंटी आज भी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक मानी जाती है। अमेरिका को सब-प्राइम लोन संकट और Lehman Brothers जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाओं के गिरने से पूरी दुनिया हिल गई थी।

लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब लोगों की नौकरियाँ गईं और खर्च कम होने लगा। लोगों ने घर खरीदना बंद किया, कार खरीदना बंद किया और खर्च सीमित कर दिया। बाजार में मांग घटी, तो उत्पादन भी घट गया और कंपनियों संकट में आ गईं। यानी अर्थव्यवस्था का असली इंजन आम आदमी का खर्च है। अगर लोगों की जेब कमजोर होती है, तो बड़े-बड़े उद्योग भी लंबे समय तक नहीं टिक सकते। आज का खतरा थोड़ा अलग है। यह अचानक आने वाला संकट नहीं है। यह धीरे-धीरे बढ़ने वाला देवाव है। इसलिए इसे साइलेंट रिसेशन कहा जा सकता है।

साइलेंट रिसेशन आखिर है क्या? साइलेंट रिसेशन ऐसी स्थिति होती है जहाँ ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। शेयर बाजार बढ़ रहा होता है, कंपनियों का मुनाफा भी अच्छा दिखता है, लेकिन जमीन पर लोगों की वास्तविक कमाई और नौकीरी की स्थिति धीरे-धीरे कमजोर होती जाती है। मान लीजिए कोई कंपनी एआई की मदद से अपने 70 प्रतिशत कर्मचारियों को हटाकर भी काम चलाने लगे। शुरुआती समय में कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है। निवेशक खुश होंगे। शेयर की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

लेकिन वे 70 प्रतिशत लोग जो पहले वेतन पा रहे थे, अब बाजार में पहले जैसे ग्राहक नहीं रहेंगे। वे नया घर खरीदने से बचेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बच्चों की महंगी पढ़ाई कम करेंगे और खर्च घटा देंगे।

धीरे-धीरे इसका असर हर क्षेत्र में फैलने लगेगा।

विशेष चिंता की बात यह है कि एआई सबसे पहले उन्हीं नौकरियों को प्रभावित कर रहा है, जो दोहराव वाले काम हैं। और भारत का सर्विस सेक्टर काफी हद तक इसी मॉडल पर आधारित है। BPO, बैंक ऑफिस, बेसिक कोडिंग, डेटा एंट्री और ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में करोड़ों युवा काम करते हैं। अगर कोई कंपनी पहले 100 कर्मचारियों से काम कर रही थी और अब 25-30 कर्मचारियों और एआई टूल्स से वही काम करने लगे, तो कंपनी का खर्च जरूर कम होगा। लेकिन बाकी लोगों की कमाई भी खत्म हो जाएगी। यहाँ से समस्या केवल रोजगार की नहीं रहती, बल्कि बाजार की मांग की बन जाती है।

2008 की मंटी ने दुनिया को क्या सिखाया था?

2008 की वैश्विक आर्थिक मंटी आज भी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक मानी जाती है। अमेरिका को सब-प्राइम लोन संकट और Lehman Brothers जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाओं के गिरने से पूरी दुनिया हिल गई थी।

लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब लोगों की नौकरियाँ गईं और खर्च कम होने लगा। लोगों ने घर खरीदना बंद किया, कार खरीदना बंद किया और खर्च सीमित कर दिया। बाजार में मांग घटी, तो उत्पादन भी घट गया और कंपनियों संकट में आ गईं। यानी अर्थव्यवस्था का असली इंजन आम आदमी का खर्च है। अगर लोगों की जेब कमजोर होती है, तो बड़े-बड़े उद्योग भी लंबे समय तक नहीं टिक सकते। आज का खतरा थोड़ा अलग है। यह अचानक आने वाला संकट नहीं है। यह धीरे-धीरे बढ़ने वाला देवाव है। इसलिए इसे साइलेंट रिसेशन कहा जा सकता है।

साइलेंट रिसेशन आखिर है क्या? साइलेंट रिसेशन ऐसी स्थिति होती है जहाँ ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। शेयर बाजार बढ़ रहा होता है, कंपनियों का मुनाफा भी अच्छा दिखता है, लेकिन जमीन पर लोगों की वास्तविक कमाई और नौकीरी की स्थिति धीरे-धीरे कमजोर होती जाती है। मान लीजिए कोई कंपनी एआई की मदद से अपने 70 प्रतिशत कर्मचारियों को हटाकर भी काम चलाने लगे। शुरुआती समय में कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है। निवेशक खुश होंगे। शेयर की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

लेकिन वे 70 प्रतिशत लोग जो पहले वेतन पा रहे थे, अब बाजार में पहले जैसे ग्राहक नहीं रहेंगे। वे नया घर खरीदने से बचेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बच्चों की महंगी पढ़ाई कम करेंगे और खर्च घटा देंगे।

पर पड़ेगा:-

रियल एस्टेट की मांग घटेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रभावित होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा।

खुदरा बाजार कमजोर होगा। सबसे पहले छोटे और मध्यम उद्योग प्रभावित होंगे।

यह असर धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए शुरुआत में दिखाई नहीं देता। लेकिन अंदर ही अंदर पूरी आर्थिक गति कमजोर होने लगती है।

आज कंपनियाँ एआई को खर्च कम करने के साधन के रूप में देख रही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास भी है।

जिस कर्मचारी को हटाकर कंपनी पैसा बचा रही है, वही व्यक्ति बाजार में उसका ग्राहक भी था।

आर्थिक चक्र कुछ इस तरह चलता है:-

कर्मचारी आय खर्च बाजार कंपनी की कमाई

अगर इस चक्र को पहली कड़ी कमजोर हो जाती है, तो आखिर में कंपनियों की कमाई भी प्रभावित होने लगती है।

यानी कंपनियाँ अल्पकालिक मुनाफे के लिए दीर्घकालिक बाजार को कमजोर कर सकती हैं।

क्या एआई अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ाएगा? Oxford Economics और OECD जैसी संस्थाओं ने कई बार चेतावनी दी है कि एआई से उत्पादकता तो बढ़ेगी, लेकिन अगर सही नीतियाँ नहीं बनीं तो असमानता भी तेजी से बढ़ सकती है।

तकनीक का सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास पूँजी, उच्च कौशल और डेटा का नियंत्रण है। दूसरी तरफ कम और मध्यम कौशल वाले लोगों पर दबाव बढ़ सकता है।

दुनिया पहले ही "K-shaped recovery" देख चुकी है, जहाँ समाज का एक वर्ग तेजी से ऊपर जाता है जबकि दूसरा वर्ग पीछे छूटता जाता है। एआई इस दूरी को और बढ़ा सकता है।

समाधान क्या हो सकते हैं? इस समस्या का समाधान एआई को रोकना नहीं है। तकनीक को रोकना नहीं जा सकता। असली सवाल यह है कि उसका इस्तेमाल किस तरह कर लिया जाए।

1. बड़े स्तर पर नई स्किल सिखाने की जरूरत

सरकार और कंपनियों को मिलकर लोगों को नए कौशल सिखाने होंगे। डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिस्टिमीटी, रोबोटिक्स, एआई मैनेजमेंट, हेल्थ टेक और ग्रीन टेक जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

2. ईंसान और एआई साथ काम करें

एआई को ईंसानों की जगह लेने

वाली तकनीक नहीं, बल्कि ईंसानों की क्षमता बढ़ाने के साथ उनके सहयोगी के तौर पर तकनीक के रूप में अपनाया होगा।

3. एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना

भारत में एमएसएमई सेक्टर लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। अगर छोटे उद्योग कमजोर होते हैं, तो रोजगार संकट और गहरा सकता है।

4. Universal Basic Income जैसे विचारों पर चर्चा

दुनिया के कई देशों में अब न्यूनतम आय सुरक्षा यानी उन्डरग्राउंड फ्लोर पर गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है।

5. आम आदमी की क्रय शक्ति बचाना सबसे जरूरी

किसी भी आर्थिक नीति का अंतिम उद्देश्य केवल जीडीपी बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की कमाई और खरीदने की क्षमता को मजबूत रखना होना चाहिए।

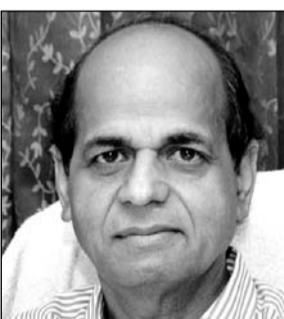
एआई मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक बन सकता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और उत्पादन में बड़े बदलाव ला सकता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल केवल लागत घटाने और ईंसानी श्रम को हटाने के लिए किया गया, तो यह आर्थिक संतुलन को कमजोर भी कर सकता है।

दुनिया की अर्थव्यवस्था मशीनों से नहीं चलती। वह लोगों की कमाई, उनके धरोरे और उनके खर्च से चलती है। अगर बड़ी संख्या में लोग आर्थिक चक्र से बाहर होने लगते हैं, तो विकास की रफ्तार धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाएगी, चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो।

चीन की अदालतों ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर किसी कर्मचारी को नौकीरी से निकालना या उसके पद और वेतन में भारी कटौती करना अवैध है कि उसका कार्य अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। अदालतों का मानना है कि तकनीकी प्रगति और स्वचालन के बावजूद कर्मचारियों के श्रम अधिकारों की रक्षा करना नियोजकों को ही जिम्मेदार है, और एआई को मानव कर्मचारियों के स्थान पर लाने मात्र को नौकीरी समाप्त करने का वैध आधार नहीं माना जा सकता। दुनिया के सभी देशों को भी ऐसी नीतियों पर विचार करना चाहिए। इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत तकनीकी प्रगति और मानवीय संतुलन के बीच सही रास्ता खोजने की है। भविष्य केवल एआई का नहीं है, बल्कि ईंसान और एआई के साथ मिलकर आगे बढ़ने का है।

-रोटैरियन सुनील दत्त गोयल, महानिदेशक, इमपीरियल बैंकर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

उड़ान के लिए खतरा बनते पक्षी



डॉ. कैलाश चंद्र सैनी

आसमान में उड़ते पक्षी विमान सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बन सकते हैं। हर वर्ष होने वाली सैकड़ों बर्ड स्ट्राइक की घटनाएँ यह बताती हैं कि यह महज संयोग नहीं, बल्कि हमारी पर्यावरणीय और प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है।

तापतलाह का परिणाम है। प्राथमिक दौर में विमानों की गति कम थी। पक्षियों को रास्ते से हटने का पर्याप्त समय मिल जाता था और नुकसान अधिकतर विंडशील्ड तक सीमित रहता था। लेकिन जेट युग ने इस समीकरण को बदल दिया।

आज के आधुनिक विमान अत्यंत तीव्र गति से उड़ते हैं। उनके टर्बाइन इंजन हल्के, जलिल और अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसी स्थिति में एक छोटा-सा पक्षी भी जब विमान से टकराता है, तो उसका प्रभाव किसी प्रक्षेप्य (मिसाइल) जैसा हो सकता है।

कौन है ये 'अनचाहे हवाई यात्री'? यह समझना जरूरी है कि पक्षी कभी जानबूझकर विमानों से नहीं

समस्या जो केवल जयपुर या भारत तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक नागरिक उड्डयन उद्योग के लिए एक महंगी और जानलेवा चुनौती बन चुकी है। भारत में हर वर्ष एक हजार से अधिक बर्ड स्ट्राइक की घटनाएँ दर्ज होती हैं। यह संख्या अपने-बताती है कि हमारे हवाई सुरक्षित प्रबंधन में अभी भी कई खामियाँ मौजूद हैं।

रफ्तार की अपनी कीमत होती है विमानों और पक्षियों का यह टकराव उतना ही पुराना है जितना उड़ान का इतिहास। विडंबना यह